

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गबोकारो जिला की ग्रामीण जनजातीय महिलाओं के जीवन पर प्रभाव का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ० इन्दिरा श्रीवास्तव

एसो० प्रोफेसर  
समाजशास्त्र विभाग  
ईश्वर शरण पी०जी० कालेज, प्रयागराज  
इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय, प्रयागराज

नीतू शुक्ला

शोध छात्रा  
समाजशास्त्र विभाग  
ईश्वर शरण पी०जी० कालेज, प्रयागराज  
इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय



सारांश—

ग्रामीण जनजातीय महिलाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम प्रारम्भ करने की जरूरत है। भारत की केन्द्र सरकार के द्वारा 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरूवात की गयी थी। जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनजातीय महिलाओं को रोजगार एवं मिट्टी के चूल्हे से मुक्ति मिल सके। यह शोध प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से ग्रामीण जनजातीय महिलाओं के जीवन जीने के तरीके को समझना है। यह वर्णनात्मक शोध पत्र झारखण्ड के बोकारो जिले के मोहाल गांव की जनजातीय महिलाओं पर किया गया है। इसके अन्तर्गत मोहाल गांव की ग्रामीण जनजातीय महिलाओं पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रभाव और उनके जीवन और आजीविका पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करता है। जिसमें इस गांव की 50 ग्रामीण जनजातीय महिला उत्तरदात्रियों से एक सरंचित साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग करके आंकड़ों को एकत्र किया गया है। अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से ग्रामीण जनजातीय महिलाओं के जीवन एवं व्यवहार में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है।

संकेत शब्द:—प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पी०एम०यू०वाई०) ग्रामीण महिलाओं, आजीविका में परिवर्तन स्वच्छ ईंधन, एलपीजी रिफिल।

**प्रस्तावना—**

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केन्द्र सरकार द्वारा बीपीएल परिवार की महिलाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को शुरू की गयी योजना है। इस योजना के अन्तर्गत बीपीएल परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस सिलेण्डर मिल रहा है। इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया क्षेत्र में हुई। जिसका नारा “स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन” था। इस योजना की पात्र महिलाओं को उनके खाते में 1600 रुपये की राशि दी जाती है। आरम्भ में यह योजना 5 करोड़ बीपीएल परिवार को कवर कर रही थी, लेकिन 2019–20 में संशोधन के बाद इस योजना के अन्तर्गत 8 करोड़ परिवार को कवर किया जा रहा है। इस योजना का लाभ सोसियो इकोनामिक एण्ड कास्ट सेंसस (एसईसीसी-2011) लिस्टेड हो, प्रधानमंत्री आवास योजना में सभी एससी, एसटी परिवार के लोग, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग या अंत्योदय योजना के अन्तर्गत आने वाले लोगों, वनवासी एवं अधिकांश पिछड़े वर्ग के लोग ले सकते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने एलपीजी उज्ज्वला योजना ने एलपीजी की लागत को बहुत कम कर दिया है। पहले एलपीजी गैस कनेक्शन कराने के लिए 4000 से 5000 रुपये खर्च करना पड़ता था। बल्कि थोक खरीद ने इसे घटाकर 3200- /रुपये कर दिया है। इस योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा लाभार्थियों को आधा पैसा एक मुक्त अनुदान के रूप में मिल जाता है। महिला उपयोगकर्ता को एलपीजी गैस और पहली रिफिल की कुछ लागत 1600 रुपये पड़ती है। इसके लिए तेल विपणन निगम (ओएमसी) आसान मासिक किस्त अर्थात् ईएमआई विकल्प दे रही है। महिला द्वारा लिया गया ऋण रिफिलिंग वसूल जाने के बाद धनजारी रहता है और महिला उपयोक्ता के बैंक में स्थानान्तरित कर दिया जाता है।

ग्रामीण महिलाओं को समाज में निम्न स्तर से उच्च स्तर में लाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनायी गयी है। पीएमयूवाई ग्रामीण लोगों को घरेलू वायु प्रदूषण की समस्या को कम करने के साथ-साथ अधिक सशक्त करने के लिए उत्कृष्ट प्रयास हैं, उज्ज्वला योजना की प्राप्तकर्ता महिलाएं कम जागरूक हैं। अतः आज भी कुछ गांवों में पारम्परिक चूल्हे का उपयोग हो रहा है। जिसके कारण वे अपने स्वास्थ्य, पर्यावरण और सशक्तिकरण के महत्व को अनदेखा कर रहे हैं।

**साहित्य पुनरावलोकन—**

- नंदा, बी0सी0 प्रधान (2019) ने बताया कि भारत में एक बड़ा हिस्सा अपनी रसोई में ठोस एवं बायोमास जैसी अशुद्ध ईंधन का उपयोग करती है। जिसमें उनके स्वास्थ्य पर खतरा है।

- एस0 सिंह तथा पी0 दीक्षित (2019) ने अपने लेख में बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बाद भी ग्रामीण परिवार के लोग ठोस ईंधन का उपयोग कर रहे हैं।
- त्रिपाठी (2019) ने अपने लेख में बताया कि पारम्परिक ईंधन का उपयोग महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में बाधा डालती है, क्योंकि महिलाओं द्वारा ईंधन को इकट्ठा करने में प्रतिदिन का अधिकांश समय बर्बाद होता है।
- अग्रवाल, कुमार और तिवारी (2018) ने अपने लेख में बताया कि घरेलू वायु प्रदूषण के कारण इन ईंधनों का निरन्तर उपयोग महिलाओं और उनके परिवार के स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित करता है। जिससे फेफड़ों और हृदय संबंधित रोग होते हैं।
- शर्मा, पारिख और सिंह (2019) ने अपने लेख में बताया कि घरेलू वायु प्रदूषण के कारण भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 5 लाख से 10 लाख लोगों की मौत हो रही है।
- पवन पाण्डेय और सुश्रुत शर्मा (2017) ने अपने लेख में बताया कि स्वास्थ्य की स्थिति बीमारियों के इलाज करने से नहीं बल्कि प्रेरक और निवारक उपायों को अपनाने से होती है। नागरिक स्वस्थ आदतों के बारे में जागरूक हो और ऐसी आदतों के बारे में जागरूक हो और ऐसा वातावरण मौजूद हो जो ऐसी आदतों को अपनाने को प्रोत्साहित करता है। ग्रामीण महिलाएं घर पर आसान एवं मुफ्त उपलब्ध ईंधन का आज भी उपयोग कर रही हैं। गैस की बढ़ती कीमत के कारण एलपीजी सिलेण्डर का उपयोग कम कर रही हैं। वह यह भी सोचती हैं कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेण्डर रिफिल कराने से आजीविका को बदलने में मदद नहीं मिल सकती है। अधिकतर ग्रामीण महिलाएं अशिक्षित हैं और उनके पास रोजगार कौशल नहीं है, उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलेगी वे कृषि कार्य और मजदूरी ही कर सकते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को झारखण्ड के बोकारो जिले के मोहाल गांव की जनजातीय महिलाओं के बीच व्यवहार परिवर्तन पर इसके प्रभाव पर बहुत कम शोध किया गया था, इसलिए शोधकर्ता इस विषय पर अध्ययन करना चाहती हैं।

#### अध्ययन का उद्देश्य—

इस अध्ययन का निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

1. अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण जनजातीय महिला उत्तरदात्रियों के जनसंख्याकीय प्रोफाइल का अध्ययन करना।
2. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और ग्रामीण जनजातीय महिलाओं के बीच व्यवहार परिवर्तन पर इसके प्रभाव का पता लगाना।

#### अनुसंधान पद्धति—

उद्देश्य की दृष्टि से वर्तमान अध्ययन एक अनुभवजन्य प्रकार का है। जिसमें आंकड़ों को एकत्र करने के लिए अन्वेषणात्मक एवं वर्णनात्मक शोध अभिकल्प का अनुसरण किया गया है। यह अध्ययन झारखण्ड के बोकारो जनपद के मोहाल गांव की जनजातीय महिलाओं पर आधारित है। जिन्हें घर पर भोजन बनाने के लिए पीएमयूवाई के तहत एलपीजी कनेक्शन प्राप्त हुआ है। यह अध्ययन पूर्णतः प्राथमिक डाटा पर आधारित है। तथ्य संकलन की प्रमुख प्रविधि के रूप में साक्षात्कार अनुसूची एवं उद्देश्यात्मक निर्देशन का प्रयोग करके 50 परिवारों में प्रत्येक परिवार की एक महिला का चयन किया गया है।

#### परिणाम एवं विश्लेषण-

अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण जनजातीय महिला उत्तरदात्रियों के जनसांख्यिकीय प्रोफाइल को सारणी 1, 2, 3 एवं 4 में और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रभाव एवं ग्रामीण जनजातीय महिलाओं के बीच व्यवहार परिवर्तन पर इसके प्रभाव को सारणी 5, 6, 7, 8 एवं 9 में बताया गया है।

ग्रामीण जनजातीय महिलाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम प्रारम्भ करने की जरूरत है। भारत की केन्द्र सरकार के द्वारा 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरूवात की गयी थी। जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनजातीय महिलाओं को रोजगार एवं मिट्टी के चूल्हे से मुक्ति मिल सके।

इस योजना की शुरूआत उत्तर प्रदेश के बलिया क्षेत्र में हुई। जिसका नारा "स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन" था। इस योजना की पात्र महिलाओं को उनके खाते में 1600 रुपये की राशि दी जाती है। आरम्भ में यह योजना 5 करोड़ बीपीएल परिवार को कवर कर रही थी, लेकिन 2019-20 में संशोधन के बाद इस योजना के अन्तर्गत 8 करोड़ परिवार को कवर किया जा रहा है।

#### सारणी संख्या-1

##### उम्र के आधार पर उत्तरदात्रियों का विवरण

उम्र समूह वर्षों में	आवृत्ति	प्रतिशत
18-29	10	20
30-39	20	40
40-49	14	28
50 या 50 वर्षों से अधिक	6	12
योग	50	100

उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 40 प्रतिशत महिलाओं की आयु (30-39) वर्ष के बीच है। अतः इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अधिकतर महिलाएं (30-39) वर्षों के बीच हैं।

#### सारणी संख्या-2

##### शैक्षिक स्तर के आधार पर उत्तरदात्रियों का विवरण

शैक्षिक स्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
अशिक्षित	35	70
प्राथमिक शिक्षा	7	14
उच्च प्राथमिक शिक्षा	3	6
हाईस्कूल	2	4
इण्टरमीडिएट	2	4
स्नातक	1	2
योग	<b>50</b>	<b>100</b>

उपरोक्त सारणी के परिणामों से महिला उत्तरदात्रियों का शैक्षिक स्तर पता चलता है, जिसमें 70 प्रतिशत अशिक्षित, 14 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा, 6 प्रतिशत उच्च प्राथमिक शिक्षा, 4 प्रतिशत हाईस्कूल, 4 प्रतिशत इण्टरमीडिएट और 2 प्रतिशत स्नातक महिलाओं द्वारा किया गया है। अतः इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अधिकतर (70 प्रतिशत) महिलाएं अशिक्षित श्रेणी में हैं।

#### सारणी संख्या-3

##### उत्तरदात्रियों के परिवार सदस्यों की संख्या

सदस्यों की संख्या	आवृत्ति	प्रतिशत
1-4	18	36
5-8	28	56
9-12	4	8
योग	<b>50</b>	<b>100</b>

उपरोक्त सारणी के परिणामों से महिला उत्तरदात्रियों के परिवारों की सदस्य संख्या पता चलती है जिसमें 1-4 सदस्यों वाले परिवार का 36 प्रतिशत, 5-8 सदस्यों वाले परिवार का 56 प्रतिशत और 9-12 सदस्यों वाले परिवार का 8 प्रतिशत है। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है अधिकतर सदस्य वाले परिवार की संख्या (5-8) है।

सारणी संख्या-4  
उत्तरदात्रियों के परिवार की मासिक आय का विवरण

मासिक आय	आवृत्ति	प्रतिशत
0-4999	18	36
5000-9999	21	42
10000-14999	8	16
15000 से अधिक	3	6
योग	<b>50</b>	<b>100</b>

उपरोक्त सारणी के परिणामों से स्पष्ट होता है कि उत्तरदात्रियों के परिवार की मासिक आय 0-4999 के बीच 36 प्रतिशत, 5000-9999 के बीच 42 प्रतिशत, 10000-14999 के बीच 16 प्रतिशत, 15000 से अधिक में 6 प्रतिशत है। अतः उत्तरदात्रियों के परिवार की सबसे अधिक आय 5000-10000 के बीच एवं सबसे कम 15000 से अधिक मासिक आय वाले है।

सारणी संख्या-5  
उत्तरदात्रियों की एक वर्ष में एलपीजी रिफिल की संख्या

रिफिल की संख्या	आवृत्ति	प्रतिशत
1-2	22	44
3-5	14	28
6-8	10	20
9-12	4	8
योग	<b>50</b>	<b>100</b>

उपरोक्त सारणी के परिणामों से स्पष्ट होता है कि उत्तरदात्रियों को एक वर्ष में एलपीजी रिफिल की संख्या 1-2 के बीच 44 प्रतिशत, 3-5 के बीच 28 प्रतिशत, 6-8 के बीच 20 प्रतिशत और 9-12 के बीच 8 प्रतिशत है। अतः सबसे अधिक लोग साल भर में 1-2 सिलेण्डर रिफिल करा रहे है जिसका मुख्य कारण गैस सिलेण्डर का महंगा होना है।

सारणी संख्या-6  
उत्तरदात्रियों द्वारा मिट्टी के चूल्हे का उपयोग

मिट्टी के चूल्हों का उपयोग	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	28	56

नहीं	22	44
योग	<b>50</b>	<b>100</b>

उपरोक्त सारणी के परिणामों से स्पष्ट होता है कि पीएमयूवाई योजना का लाभ मिलने के बाद भी 56 प्रतिशत महिला उत्तरदात्रियों के द्वारा मिट्टी के चूल्हे का उपयोग किया जा रहा है जबकि 44 प्रतिशत महिला उत्तरदात्रियों द्वारा केवल एलपीजी गैस सिलेण्डर का ही उपयोग किया जा रहा है।

सारणी संख्या-7

उत्तरदात्रियों का आर्थिक गतिविधियों में सहयोग

आर्थिक गतिविधियों में उपयोग	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	26	52
नहीं	24	44
योग	<b>50</b>	<b>100</b>

उपरोक्त सारणी के परिणाम से स्पष्ट होता है कि 52 प्रतिशत महिला उत्तरदात्री आर्थिक गतिविधियों में सहयोग कर रही है जबकि 48 प्रतिशत महिला उत्तरदात्री गृहणी है।

सारणी संख्या-8

व्यवसाय के आधार पर उत्तरदात्रियों का विवरण

व्यवसाय का प्रकार	आवृत्ति	प्रतिशत
कृषि	3	11.54
मजदूरी	11	42.31
दुकानदार	4	15.38
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	2	7.69
स्कूल में खाना बनाना	1	3.85
सिलाई	2	7.69
अन्य	3	11.54
योग	<b>26</b>	<b>100</b>

उपरोक्त सारणी के परिणामों से स्पष्ट होता है कि 11.54 प्रतिशत, महिला उत्तरदात्री कृषि क्षेत्र में 42.31 प्रतिशत मजदूरी, 15.38 प्रतिशत दुकानदार, 7.69 प्रतिशत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 3.



85 प्रतिशत स्कूल में खाना बनाने का, 7.69 प्रतिशत सिलाई और 11.59 अन्य कार्यों में संलग्न है।

सारणी संख्या-9  
उत्तरदात्रियों के जीवन में परिवर्तन

जीवन में परिवर्तन	आवृत्ति	प्रतिशत
राख व धुआ से मुक्ति	12	24
स्वच्छ एवं स्वास्थ्य वातावरण	11	22
समय की बचत	7	14
कोई बदलाव नहीं	20	40
<b>योग</b>	<b>26</b>	<b>100</b>

उपरोक्त सारणी के परिणामों से स्पष्ट होता है कि पीएमयूवाई योजना का लाभ मिलने के बाद 60 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के जीवन में बदलाव आया जबकि 40 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया।

**निष्कर्ष-**

इस अध्ययन में विश्लेषण के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि पीएमयूवाई उन सभी ग्रामीण जनजातीय महिलाओं के लिए एक महत्वकांक्षी योजना है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण जनजातीय महिलाओं को अशुद्ध या ठोस ईशान का उपयोग करने के अधिक परिश्रम से बचाया जा रहा है। 1 मई 2016 को गैस का दाम लगभग 577 रु0 था। जबकि आज गैस का दाम 1156 है। जिसको रिफिल कराना ग्रामीण जनजातीय महिलाओं के लिए अत्यन्त कठिन है। ग्रामीण जनजातीय महिलाएं 400/-रु0 की लकड़ी एक माह तक चलाती है। जबकि गैस रिफिल कराना उनके लिए त्रिगुना कीमत अदा करना है। इस प्रकार ग्रामीण जनजातीय महिलाओं के जीवन एवं व्यवहार में कम परिवर्तन आया है।

**सुझाव-**

1. पीएमयूवाई योजना का लाभ मिलने के बाद ग्रामीण जनजातीय महिलाओं को उच्च लागत, 1156/-रु0 में गैस रिफिल कराना पड़ता है। अतः उनके लिए गैस सिलेण्डर की कीमत कम करना चाहिए।
2. पीएमयूवाई योजना के लाभार्थी 14.2 किलो का एक सिलेण्डर न लेकर यदि 5 किलो का दो सिलेण्डर ले तो उन्हें भराने एवं रिफिल कराने में सरलता होगी। क्योंकि वे 5 किलो का सिलेण्डर कम पैसे में भरा सकते हैं।



सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची :-

- Aggarwal, S., Kumar, S, & Tiwari, M. K. (2018). Decision support system for Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. Energy Policy, 118 (January), 455-461. <https://doi.org/10.1016/j.enpo.2018.04.011>.
- Hammeed, G., Orifan, M., Ijeoma, M. & Tijani, S. (2016). Assessment Of the Use of Liquefied Petroleum Gas (LPG) as Cooking Energy Source Among Rural Household in Badagry Area of Lagos State Technology and Sciences (ASRJETS) American Scientific Research Jindal for Engineering, 18 (1), pp (16-28). Retrieved form [https:// asrjetsjournal.org/](https://asrjetsjournal.org/).
- Kar A, Pachauri S, Bailis R, Zerriffi H. (2019), Using Sales Data TO Assess Cooking Gas Adoption and the Impact of India's Ujjwala Programme in Rural Karnataka Nature Energy 4 (9) pp (806-814).
- Nanda, B.C., (2019). Pradhan Mantri Ujjwala Yojana as a tool of women empowerment: An assessment. Mahila Pratishtha, 4 (4), 231-241.
- Sahoo K, Manoj, Patel Palak and Patel, Rootu: Grassroots Energy security for india's poor and women empowerment: An assessment fo Pradhan Mantri Ujjawala Yojana. ISSN 2231-0924 Volume 8, No. 2 July-December 2018, pp-18-27.
- Sharma, Ashutosh and Singh, Chandraeshkar. "Transition to LPG for cooking. A case Study from two states of India "Energy for sustainable development , volume 51, suggest 2019, page (63-72).
- Singh S. & Dixit P. (2019) "Impact of household air pollution exposure on rural India". A Systematic review, environment conservation Journal 20 (1 & 2) pp (115-132).
- Tripathi, S.K. Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY): Women Empowerment in India EI SSUL 3. SEr. II (March-2019, pp-81-83). <https://doi.org/10.9790/487x-2103028163>.